भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1429**
वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

समुद्री खाद्य निर्यात पर अमरीकी शुल्कों का असर

1429. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री तनुज पुनिया:
श्री एंटो एन्टोनी:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्री खाद्य उद्योग पर अमरीकी शुल्कों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) शिपमेंट, आपूर्ति शृंखला व्यवधान और बढ़ते वित्तीय दबाव से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) सितंबर, 2025 से समुद्री खाद्य उद्योग को हुए वित्तीय नुकसान का ब्यौरा क्या है; और
(घ) मात्स्यिकी क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों को सरकार क्या मदद दे रही है जिनकी रोजी-रोटी पर इस शुल्क की वजह से असर पड़ा है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) : सरकार भारत के समुद्री निर्यात पर निरंतर निगरानी रखती है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कदम उठाती है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, अप्रैल-अक्टूबर और सितंबर-

अक्टूबर, 2025 की अवधि में, दुनिया भर में भारत को समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। विश्व को भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात का विवरण (मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में) निम्नवत है:

	अप्रैल-अक्टूबर 2024	अप्रैल-अक्टूबर 2025	सितंबर-अक्टूबर 2024	सितंबर-अक्टूबर 2025
निर्यात	4.20	4.87	1.44	1.68

स्त्रोतः डीजीसीआईएस

सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के उभरते प्रभाव का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों के साथ संपर्क में है। सरकार एक व्यापक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन बातचीत, आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन उपाय जो हमारे निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान करता है, नए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना और मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग करना शामिल है। निरंतर प्रयासों के माध्यम से, हाल ही में यूरोपीय संघ और रूस को निर्यात के लिए सूचीबद्ध मत्स्य पालन संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है।

मत्स्य पालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए कुल 21274.13 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे इस क्षेत्र में भारत का निर्यात वित्तीय वर्ष 2013-14 के 30,213 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपये हो गया है, जो दोगुने से भी ज्यादा है, जिसमें मूल्यवर्धित उत्पादों का हिस्सा 2% से बढ़कर 11% हो गया है।

यह उम्मीद की जाती है कि सामूहिक रूप से इन उपायों से भारत के समुद्री निर्यात में विविधीकरण और लचीलापन बढ़ेगा।

*****